गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 340 | दि. 11-04-2019 गुरुवार | वि.सं. 2075 | चैत्र सुद-०६ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

वोट से पहले केन्द्र सरकार को चोट

SC ने राफेल के लीक दस्तावेज माने वैध, फिर से होगी सुनवाई

जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी : सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राफेल डील मामले में करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया है। सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली ३ सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लीक दस्तावेजों के आधार पर रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये दस्तावेज प्रिविलेज्ड (विशेषाधिकार वाला गोपनीय) दस्तावेज है और इस कारण रिव्यू पिटिशन खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस के. एम. जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई ऐक्ट २००५ में आया है और ये एक क्रांतिकारी कदम था ऐसे में हम पीछे नहीं जा सकते। सरकार ने कहा था कि जो दस्तावेज प्रशांत भूषण ने रिव्यू पिटिशन के साथ पेश किए हैं वह प्रिविलेज्ड दस्तावेज है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है ये दस्तावेज गोपनीय है और आरटीआई के अपवाद में है साथ ही एविडेंस ऐक्ट के तहत गोपनीय दस्तावेज है। इंडियन एविडेंस ऐक्ट के तहत गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता। जो दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, दो देशों के संबंध पर असर डालता हो उन्हें गोपनीय दस्तावेज माना गया है। अनुच्छेद-१९ (२) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार पर वाजिब रोक की बात है। जहां देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होगा वह रोक के दायरे में आएगा। आरटीआई के तहत भी देश की संप्रभुता से जुड़े मामले को अपवाद माना गया है। सरकारी गोपनीयता कानून की धारा-३ और ५ में भी रोक है। इस दौरान याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ये तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। जो दस्तावेज पहले से लोगों के सामने है उस पर कोर्ट विचार न करें क्योंकि ये प्रिविलेज्ड दस्तावेज है, यह बेकार की दलील है। एविडेंस ऐक्ट के तहत जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में लाने से रोका गया है, वे वैसे दस्तावेज हैं जो पहले से गोपनीय हैं और प्रकाशित नहीं हुए हैं लेकिन इस मामले में डिफेंस के दस्तोवज पहले से लोगों के सामने है। केंद्र सरकार ने अभी तक मामले में केस दर्ज नहीं किया। पहली बार १८ नवंबर को ये रिपोर्ट वेबसाइट पर छपी। सीएजी रिपोर्ट सरकार ने पेश किया है। उसमें डिफेंस डील से संबंधित जानकारी है। भूषण की दलील थी कि सरकार ने खुद सीएजी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया। ऐसे में उनकी ओर से पेश दस्तावेज को प्रिविलेज्ड दस्तावेज कैसे कह सकते हैं। उधर प्रेस काउंसिल कहता है कि मीडिया कर्मी सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है। एसपी गुप्ता से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि कोई दस्तावेज गोपनीय है या नहीं और देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस बात को पब्लिक इंट्रेस्ट में परखा जाएगा। इस मामले में दस्तावेज पहले से पब्लिक में है। सरकार खुद की अपने लोगों को इस तरह की जानकारी लीक करती रही है। रक्षा मंत्री की फाइल नोटिंग भी इसी तरह लीक की गई। २ जी मामले और कोल ब्लॉक मामले में भी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विसल ब्लोअर का नाम बाहर लाने की जरूरत नहीं है। अगर दस्तावेज केस के लिए जरूरी है तो यह बात औचित्यहीन है कि उसे कहां से और कैसे लाया गया है। भूषण ने कहा कि वियतनाम वॉर से संबंधित पेंटागन के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और यूएस सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण दस्तावेज गोपनीय रखने की दलील खारिज कर दी गई थी। सरकार की दलील पूर्वाग्रह वाला है और टिकने वाला नहीं है क्योंकि यहां दस्तावेज को विशेषाधिकार वाले दायरे में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये पहले ही प्रकाशित है। अगर दस्तावेज करप्शन के केस के लिए औचित्यपूर्ण है तो इस बात का मतलब नहीं रह जाता कि ये कहां से लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में जांच की गुहार से संबंधित अर्जी को १४ दिसंबर २०१८ को खारिज कर दिया था, जिसके बाद रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है जिस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने मामले की सुनवाई हुई थी। १४ मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस ऐतराज पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया था कि क्या प्रिविलेज्ड दस्तावेज पर विचार करते हुए रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई हो या नहीं।

अमेठी की सड़कों पर उतरा गांधी परिवार

लोकसभा चुनाव : अमेठी से राहुल गांधी ने किया नामांकन

नामांकन से पहले करीब तीन किलोमीटर लंबा रोड शो करके राहुल ने अपनी ताकत का अहसास कराया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अमेठी,

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड के बाद अब यूपी के अमेठी से भी पर्चा दाखिल कर दिया। उनके नामांकन जुलूस में सोनिया गांधी को छोड़कर समूचा गांधी परिवार अमेठी की सड़कों पर उतर आया। नामांकन से ठीक पहले आयोजित करीब तीन किलोमीटर लंबा रोड शो करके राहुल गांधी ने अपनी ताकत का अहसास कराया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ चुनावी रथ पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे रिहान और मियारा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के नामांकन करने के दौरान उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। तीन किमी लंबे इस रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं के साथ राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने हाथ हिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस झंडों और फूल-मालाओं से पाट दिया था। अमेठी में जश्न जैसा माहौल रहा। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। बता दें कि अमेठी में छह मई को वोट डाले जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में उनका मुकाबला बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी से होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले सोनिया और प्रियंका गांधी राहुल के नामांकन में शामिल होने के लिए मंगलवार रात ही अमेठी पहुंच गई थीं। रोड शो के दौरान राहुल गांधी मुंशीगंज-दरपीपुर-के रास्ते होते हुए गौरीगंज नगर तक जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अमेठी में स्मृति इरानी से मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए नामांकन भरने से ठीक पहले रोड शो के जरिए राहुल गांधी ने अपने समर्थकों को लुभाने की कोशिश की। राहुल के रोड शो में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। राहुल गांधी अमेठी से लगातार ३ बार सांसद चुने गए हैं। २००४ में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल की थी।

फिर २००९ में और २०१४ में भी वह इस सीट से संसद पहुंचे। २०१४ में बीजेपी ने राहुल के खिलाफ स्मृति इरानी को टिकट दिया था। स्मृति के लिए चुनाव प्रचार करने खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी अमेठी गए थे। इस बार भी राहुल के सामने स्मृति इरानी चुनौती देंगी। अमेठी से अपना रिश्ता दिल से होने की बात राहुल कई बार कह चुके हैं। यह सीट एक तरह से उनके परिवार की सीट रही है। राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने हाथ हिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। रोड शो के रास्ते को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस झंडों और फूल-मालाओं से पाट दिया था। अमेठी में जश्न जैसा माहौल रहा। इसी सीट से उनके चाचा संजय गांधी भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। संजय की मौत के बाद १९८१ में इस सीट पर उच-चुनाव हुए और तब राजीव गांधी से यहां से चुनकर संसद गए। राहुल-प्रियंका कई बार चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी से खास रिश्ता होने की बात करते रहे हैं।

मेरे पिता की यह कर्मभूमि थी : प्रियंका

अमेठी हमारे लिए पवित्र भूमि हैं : प्रियंका गांधी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अमेठी,

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अमेठी सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन और उससे पहले रोड शो के दौरान समूचा गांधी और वाड्रा परिवार मौजूद रहा। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रिहान और बेटी मियारा भी रोड शो में शामिल हुए। राहुल के पर्चा दाखिल करने के बाद प्रियंका ने पूरे परिवार के साथ नामांकन यात्रा में शामिल होने की वजह बताई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'कुछ रिश्ते दिल के होते हैं। आज भाई (राहुल गांधी) के नामांकन के लिए पूरा परिवार मौजूद था। मेरे पिता की यह कर्मभूमि थी, हमारे लिए पवित्र भूमि है। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रिहान और बेटी मियारा भी रोड शो में शामिल हुए। राहुल के पर्चा दाखिल करने के बाद प्रियंका ने पूरे परिवार के साथ नामांकन यात्रा में शामिल होने की वजह बताई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 'कुछ रिश्ते दिल के होते हैं। प्रियंका गांधी ने नामांकन के बाद अपने बच्चों के साथ नामांकन स्थल पर सेल्फी भी ली। बता दें कि इससे पहले केरल के वायनाड में भी राहुल गांधी के साथ उनकी बहन मौजूद थीं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका ने रोड शो भी किया था।

राहुल ने अमेठी के लोगों से छल किया : स्मृति इरानी

स्मृति इरानी का राहुल पर तंज, क्या अमेठी सिंगापुर बन गई ?

बीजेपी के ५ साल के कार्यकाल में अमेठी में काम हुआ है यहां जो भी विकास है वह बीजेपी के कारण है : स्मृति

(संपूर्ण समाचार सेवा) अमेठी,

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से पर्चा भरने के साथ ही इस हॉट सीट पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। बुधवार को एक तरफ जहां अमेठी में राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया तो वहीं दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंदी केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने उन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी पर वार करते हुए स्मृति ने उनसे तंज भरे लहजे में पूछा, क्या अमेठी सिंगापुर बन गई ? राहुल गांधी यहां समय-समय पर अमेठी को सिंगापुर बनाने का दावा करते रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को अमेठी से नामांकन किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे रिहान और मिराया भी रोड शो में शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल इस बार दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले केरल के वायनाड सीट से भी नामांकन किया है। उधर, गुरुवार को यहां से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति इरानी नामांकन करेंगी। बुधवार को इरानी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अमेठी के लोगों से छल किया है। इरानी ने कहा कि सच्चाई यह है कि बीजेपी के ५ साल के कार्यकाल में अमेठी में काम हुआ है और यहां जो भी विकास है वह बीजेपी के कारण है। अमेठी ने यह भी कहा कि वह और उनकी सरकार किसानों, गरीबों और व्यापारियों के साथ है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह साथ छोड़कर नहीं भागेंगी बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के हक की लड़ाई उनके साथ रहकर लड़ती रहेंगी। स्मृति ने इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह साथ छोड़कर नहीं भागेंगी बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों के हक की लड़ाई उनके साथ रहकर लड़ती रहेंगी। राहुल गांधी पहली बार अमेठी से २००४ में चुनाव लड़े और तब से अब तक वह यहां के सांसद हैं। आमतौर पर बाकी पार्टियां कांग्रेस को इस सीट पर वॉकओवर देती आई हैं, लेकिन २०१४ में बीजेपी ने यहां से स्मृति इरानी को उतारकर मुकाबले को काफी रोमांचक बना दिया था। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे रिहान और मिराया भी रोड शो में शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल इस बार दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले केरल के वायनाड सीट से भी नामांकन किया है। २०१४ में आम आदमी पार्टी की ओर से कवि कुमार विश्वास भी मैदान में उतरे लेकिन वह कोई खास चुनौती नहीं पेश कर सके और चौथे स्थान पर रहे।

उत्तराखंड में चुनाव प्रचार समाप्त, ११ को मतदान होगा

(संपूर्ण समाचार सेवा) देहरादून,

उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ११ अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिये पिछले एक पखवारे से चल रहा चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार शाम समाप्त हो गया। प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि शाम पांच बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्याशी जनसभाओं के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं की संख्या ७८ लाख ५६ हजार २६८ है जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ३७ लाख ११ हजार २२० है। ट्रांसजेडर मतदाताओं की संख्या २५९ है जबकि सर्विस वोटर ९०८४५ हैं। सबसे ज्यादा वोटर १८ लाख ४० हजार ७३२ हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम मतदाता १३ लाख ३७ हजार ८०३ अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में हैं। सर्वाधिक २७.४ प्रतिशत संख्या ३०-३९ आयुवर्ग के मतदाताओं की है जबकि १.६ प्रतिशत मतदाताओं की उम्र ८० वर्ष से अधिक है। पूरे राज्य में कुल ११२२९ मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से ६९७ संवेदनशील और ६५६ अतिसंवेदनशील घोषित किए गए हैं।

संपादकिय

छत्तीसगढ़ में बेलगाम होते नक्सली, सख्ती से निपटने के लिए सरकार को करना होगा सफाया

चुनाव पूर्व छत्तीसगढ़ नक्सिली हमले में भाजपा विधायक समेत चार जवान शहीद हो गए। अब वक्त आ गया है केन्द्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्तरूप से सर्च अभियान चलाकर नक्सिलयों का खातमा करें।छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी के साथ चार सुरक्षाकर्मियों की मौत नक्सलियों के फिर से सिर उठाने का संकेत होने के साथ ही इस बात का भी सूचक है कि उनका दमन किया जाना शेष है। दंतेवाड़ा की खौफनाक घटना यही रेखांकित कर रही है कि नक्सलियों का दुस्साहस कायम है और वे चुनाव प्रक्रिया के साथ कानून एवं व्यवस्था को भी चुनौती देने में समर्थ बने हुए हैं। यह सिलसिला अब थमना ही चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कुछ लगाम लगी है, लेकिन यह ठीक नहीं कि वे जब–तब हिंसक वारदात करने में समर्थ हो जाते हैं। चिंता की बात यह है कि उनके ज्यादातर हमले बारूदी सुरंगों के जरिये ही होते हैं। आखिर वे बारूदी सुरंगों का इतनी आसानी से इस्तेमाल करने में कैसे समर्थ हैं ? एक सवाल यह भी है कि उन्हें आधुनिक हथियारों और विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति कहां से हो रही है ? इन सवालों के जवाब इसलिए तलाशे जाने चाहिए, क्योंकि इस राज्य में नक्सली रह–रह कर सिर उठाकर उन दावों को चुनौती देते हैं जिनके तहत यह कहा जाता है कि उनकी ताकत कम हो रही है। नक्सली किस तरह अभी भी एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, इसका प्रमाण केवल यही नहीं है कि तमाम चौकसी के बाद भी वे जहां–तहां हमले करने में समर्थ हैं, बल्कि यह भी है कि उनके हमलों के भय से राज्य में लोकसभा चुनाव तीन चरणों में कराने पड़ रहे हैं। इसके पहले विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराने पड़े थे। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले नक्सलियों के हमले में बीएसएफ के चार जवान निशाना बने थे। जब नक्सली संगठन चुनाव के बहिष्कार की धमकी देने के साथ हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए थे तब फिर कहीं अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। जरूरी केवल यह नहीं है कि चौकसी में कमी के कारणों का पता लगाने के साथ उनका निवारण किया जाए, बल्कि यह भी है कि जिन नक्सलियों ने भाजपा विधायक के काफिले को निशाना बनाया उन्हें जितनी जल्दी संभव हो, ठिकाने लगाया जाए। इसी के साथ इसकी भी तह तक जाने की जरूरत है कि नक्सलियों ने नक्सल प्रभावित इलाके के इकलौते भाजपा विधायक को क्यों निशाना बनाया ? नक्सलियों को यह संदेश देना बहुत जरूरी है कि अगर वे हिंसा का सहारा लेने से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नक्सली किसी नरमी के हकदार इसलिए नहीं, क्योंकि वे वसूली करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए हैं और निर्धन तबके को बहकाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नक्सली पुलिस एवं सुरक्षा बलों की ओर से बनाए गए दबाव से मुक्त न होने पाएं। यह शुभ संकेत नहीं कि वे एक सप्ताह के अंदर दो बड़ी वारदात करने में सक्षम हो गए। यह जरूरी है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार नक्सलियों से निपटने की नीति को और प्रभावी बनाने पर ध्यान दे। आंतरिक सुरक्षा के मामले में संकीर्ण राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

प्रतिबद्ध न्याय पालिका का नारा

(जी.एन.एस.) जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपने राफेल राग पर लगाम लगाएंगे तब उन्होंने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा उछाला। इतना ही नहीं उन्होंने तथ्यों से मुंह चुराते हुए इस सौदे में देरी का आरोप भी मोदी सरकार पर म ?दिया, जबकि हर कोई जानता है कि मनमोहन सरकार कैसे वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली मारे बैठी रही। आखिर राहुल का रवैया खुद को जबरन सही साबित करने वाला नहीं तो और क्या है ? यह तो कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है। राफेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय को हिकारत भरी नजरों से देखना भला और क्या है ? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने यही सब तो किया था! 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी में यह प्रवृत्ति बलवती होने लगी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवाद की ओर बड रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा तो आपातकाल से पहले ही दे दिया गया था। इस नारे को कांग्रेसी सांसद शशि भूषण ने उछाला था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसका कभी विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग

पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यहां तो सिर्फ दोहरे मापदंड की बात हो रही है। इस पृष्ठभूमि में यह बताना प्रासंगिक है कि कैग जैसी संस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की और साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री ने किस तरह उसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल खडा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। सरकार के अफसर तो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं, पर कांग्रेस की मौजूदा पीडी ने राजनीतिक कारणों से संस्था के प्रति जवाहरलाल नेहरू की भावना की भी परवाह नहीं की। उसे तो बस यही चाहिए कि कोई संस्था उस व्यक्ति को राफेल मामले में दोषी ठहरा दे जिसको कांग्रेस दोषी देखना चाहती है। तभी उसे कांग्रेस के उस प्रथम परिवार के समकक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री को ला देने में सुविधा होगी। याद रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैग की रिपोर्ट के बाद अच्छा होता कि राहुल राफेल पर दोबारा चर्चा करने से बचते। बहरहाल आपातकाल तथा अन्य अनेक कारणों से इंदिरा गांधी की 1977 के चुनाव में पराजय हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तब लगा था कि कांग्रेस की इमरजेंसी की मानसिकता का खात्मा हो गया, पर कांग्रेस की नई पीडी तो उसे बनाए रखने के पक्ष में लगती है!

अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही हैं

(जी.एन.एस.) आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारणों में से एक है। यह बात शत–प्रतिशत सही है कि हमने जिस तरह की जीवनशैली अपना रखी है वह एक दिन हम सबको डुबो देगी या फिर हमारा दम घोंट देगी। अगर हम मात्र जीवन की कुछ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित होते तो भी चलता, पर अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही है। दुर्भाग्य यह है कि हम इस बदलते हालात की चर्चा तो कर रहे हैं, पर इन सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हर मौसम के बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं मिली थी ? जॉन टेंडल ने वर्ष 1850 में यह बता दिया था कि ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या ठंडी का कारण बन सकती हैं। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण

है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं जो कार्बन उत्सर्जन के खतरे को कम कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने उपयोगों के लिए भयानक रूप से जंगलों का हनन किया है। वर्ष 2017 में अकेले 390 लाख एकड वनों की कटाई हुई। मतलब एक मिनट में एक पेड काटा गया। यह कटाई हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है जिसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। मसलन टिंबर के लिए 37 फीसद वनों का हनन होता है, वहीं खेती के लिए 28 फीसद, सडक निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में करीब 140 फीसद। इसके अतिरिक्त 21 फीसद वन दावानल की भेंट चड जाते हैं। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मीट और मीट उत्पाद से जुडी हमारी खाद्य आदतें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बडा कारण हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि इनके लिए वर्ष 2030 में आज के मुकाबले 67 फीसद ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग होगा। मतलब साफ है आने वाले दिनों में ये इंसानों में संक्रमण का एक बडा कारण बनेंगे। एक आकलन है कि वर्ष 2050 तक सालाना 9.5 मिलियन लोग इसका शिकार बनेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, निर्माण कार्य एवं कंप्यूटर डाटा जो आज मात्र एक फीसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण हैं, वर्ष 2040 तक ये 14 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं यह इसलिए है, क्योंकि हम एक भोगवादी सभ्यता का बडा हिस्सा बन गए हैं। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है।जाहिर है हमें यहां प्रकृति और विज्ञान के नियमों को समझने का समय है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। अब जो चर्चा का सबसे बडा विषय होना चाहिए वह यह कि हम अपनी जीवनशैली को ढेर सारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से न देखें। संसाधनों का आवश्यकता एवं सुविधा भर उपयोग एक तरफ जहां हमें लंबा जीवन दे सकता है वहीं प्रकृति और पृथ्वी को भी विचलित नहीं करेगा। यह पूरी तरह सच है कि हमारी तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने हमें ऐसे मो ? पर पहुंचा दिया है जहां से आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीने के तौर–तरीकों में सुविधाओं से ज्यादा साधनों के उन तरीकों को अपनाएं जो सततता प्रदान कर सकते हैं।

बोटाद ब्रॉड गेज रूपांतरण प्रॉजेक्ट पूरा होने के करीब

दिसम्बर तक में अहमदाबाद-बोटाद लाइन पर ट्रेनें चलेगी

अहमदाबाद और भावनगर के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को अब आधुनिक सुविधावाली ट्रेनें मिलेगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, अहमदाबाद-भावनगर के बीच का ११४३ करोड़ रुपये का बोटाद ब्रॉड गेज रूपांतरण प्रॉजेक्ट पूरी होने की तैयारी में है, जिसकी वजह से दिसम्बर तक में अहमदाबाद-भावनगर के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को आधुनिक सुविधावाली ट्रेनें मिलेगी। अहमदाबाद-बोटाद लाइन पर स्थित १२ रेलवे स्टेशन को नया रंग रूप दिया जा रहा है। दिसम्बर तक में यह लाइन पर रेल व्यवहार शुरू होने से अहमदाबाद-भावनगर के बीच के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अहमदाबाद से भावनगर सिर्फ साढ़े तीन घंटे में पहुंच सके ऐसे टार्गेट के साथ उपरोक्त प्रॉजेक्ट संबंधी कामकाज जोर-शोर से चालू है। रेलवे ट्रैक पर बोटाद से हडाला-भाल तक के ४० किमी. के मार्ग पर सफलतापूर्वक इंजन का टेस्टिंग भी पूरा किया गया है। ट्रैक के ब्रॉड गेज रूपांतरण काम चालू है। करीब ६५ फीसदी से ज्यादा काम पूरा कर दिया गया है। यह महीने के अंत तक में और २० किमी. का मार्ग ब्रॉड गेज रूपांतरण हो जाएगा, जिसकी वजह से कुल ६० किमी. का मार्ग ब्रॉड गेज ट्रैक होगा। अहमदाबाद-बोटाद ब्रॉड गेज रूपांतरण प्रॉजेक्ट वर्ष २०१२-१३ में मंजूर हुआ था। प्रॉजेक्ट की कीमत उस समय में ८०० करोड़ रुपये अनुमान लगाया गया था। यह प्रॉजेक्ट की कीमत बढ़कर ११४३ करोड़ रुपये हुई है। यह लाइन पर स्थित १२ रेलवे स्टेशन को नया रंग रूप दिया जाएगा, जिसमें मोरैया, मटोडा, तगडी, धंधूका, सरखेज, बावला, धोलका और गोधनेश्वर शामिल है। इस बारे में अहमदाबाद रेलवे के पीआरओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि, यह मार्ग पर इलेक्ट्रीफिक्केशन का काम बाकी है। अहमदाबाद-बोटाद लाइन पर स्थित १२ रेलवे स्टेशन को नया रंग रूप दिया जा रहा है। दिसम्बर तक में यह लाइन पर रेल व्यवहार शुरू होने से अहमदाबाद-भावनगर के बीच के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अहमदाबाद से भावनगर सिर्फ साढ़े तीन घंटे में पहुंच सके ऐसे टार्गेट के साथ उपरोक्त प्रॉजेक्ट संबंधी कामकाज जोर-शोर से चालू है। रेलवे ट्रैक पर बोटाद से हडाला-भाल तक के ४० किमी. के मार्ग पर सफलतापूर्वक इंजन का टेस्टिंग भी पूरा किया गया है। ट्रैक के ब्रॉड गेज रूपांतरण काम चालू है। करीब ६५ फीसदी से ज्यादा काम पूरा कर दिया गया है। अब नए मार्ग पर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे होगा। यह काम आरवीएनएल के अलावा एक यूनिट द्वारा अलग से होगा। आगामी दिसम्बर तक में सभी काम पूरा किया जाएगा। जिसकी वजह से अहमदाबाद-भावनगर के बीच के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने जांच के आदेश दिए

हरामजादा कहने पर वाघाणी विरूद्ध जांच के आदेश : रिपोर्ट

कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष की गई शिकायत चुनाव अधिकारी द्वारा आखिरकार में कार्रवाई की गई

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी पिछले कई दिनों से बिगड़े बोल की वजह से विवाद में रहे है। हालांकि, अब तो उन्होंने सूरत में रविवार रात को एक सभा में कांग्रेस के लिए हरामजादा शब्द का प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को सूरत से भगा देने की धमकी कहने से वाघाणी ने फिर बिगड़े बोल बोलने से कांग्रेस द्वारा पूरे मामले में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की गई। जिसके संदर्भ में सूरत जिला चुनाव अधिकारी द्वारा पूरे मामले में जीतू वाघाणी के विरूद्ध जांच के आदेश दिए गए और इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। वाघाणी के विवादित, अपमानजनक और चुनाव आचारसंहिता का भंग हो इस प्रकार के बयान को लेकर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में अभी से ही हार का संकेत मिल जाने से और निराश हो गये भाजपा के नेता बिगड़े बोल बोलना बंद करे ऐसी चेतावनी दी और वाघाणी के मुद्दे पर वाघाणी सहित भाजपा माफी मांगे ऐसी मांग की गई। दूसरी तरफ, कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले में चुनाव आयोग में वाघाणी विरूद्ध शिकायत करने की कार्रवाई शुरू की गई। पूरा मामला बिगड़ने से सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने पूरे मामले में मंगलवार को जांच के आदेश दिए। चुनाव अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश देकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि, सूरत में कलेक्टर ऑफिस पर नामांकन फॉर्म भरते समय भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना संदर्भ में वाघाणी ने कांग्रेस को ऐसी खुली धमकी दी। हालांकि, राज्य का चुनाव आयोग धृतराष्ट्र के जैसे फिर एक बार इस मामले में मूक प्रेक्षक बन रहा है और ऐसी गाली बोलने पर वाघाणी के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। सूरत में ओलपाड विधानसभा मतक्षेत्र के तहत अमरोली क्षेत्र में भाजपा की महिला उम्मीदवार दर्शना जरदोश के चुनाव कार्यालय का रविवार रात को उद्घाटन करने वाघाणी आये थे। इस अवसर पर उन्होंने शुरू में कांग्रेस पर निशाना साधा और इनके कार्यकर्ताओं पर बदमाशी करने का आरोप लगाया था।

मर्सल एक ऐक्शन थ्रिलर फिल्म थी

तमिल फिल्म मर्सल के रीमेक में होंगे ऐक्टर शाहरुख खान

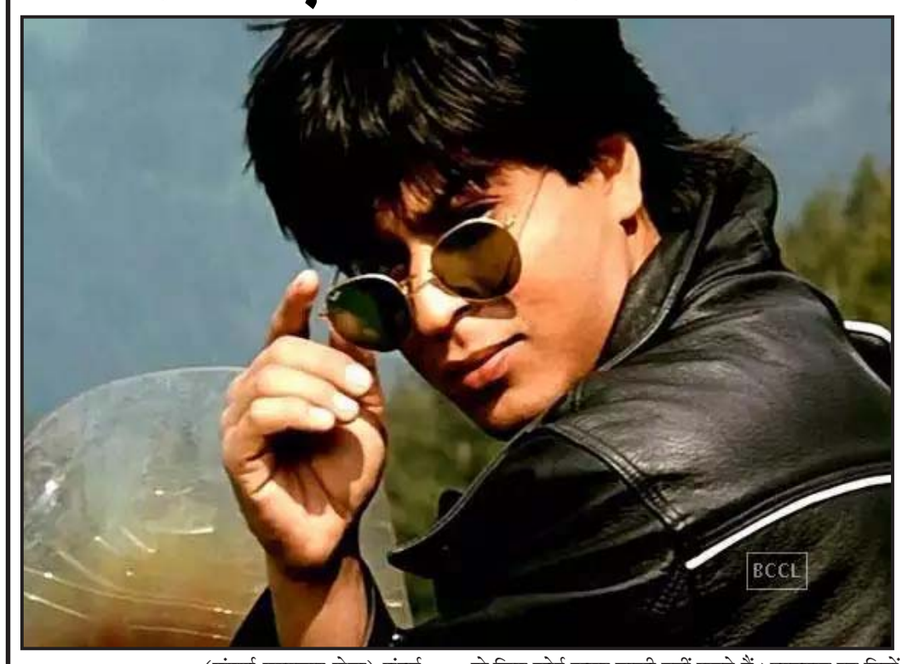

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐक्टर शाहरुख खान बॉलिवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं जिनकी दुनियाभर में काफी फैन फॉलोइंग है। किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर शाहरुख अपने रोल में पर्फेक्शन के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। शाहरुख इन दिनों अपने आने वाले प्रॉजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में ऐक्टर की चेन्नई में हुए मैच से कुछ तस्वीरें सामने आईं जिसमें वह साउथ डायरेक्टर ऐटली के साथ दिखे। ऐटली ने २०१७ में आई तमिल फिल्म मर्सल का डायरेक्शन किया था जिसमें सुपरस्टार विजय अहम रोल में थे। उसके बाद से ही इस बात की काफी चर्चा थी कि शाहरुख फिल्म के रीमेक में काम कर सकते हैं। हाल ही में ऐक्टर की चेन्नई में हुए मैच से कुछ तस्वीरें सामने आईं जिसमें वह साउथ डायरेक्टर ऐटली के साथ दिखे। ऐटली ने २०१७ में आई तमिल फिल्म मर्सल का डायरेक्शन किया था जिसमें सुपरस्टार विजय अहम रोल में थे। उसके बाद से ही इस बात की काफी चर्चा थी कि शाहरुख फिल्म के रीमेक में काम कर सकते हैं। किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर शाहरुख अपने रोल में पर्फेक्शन के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। शाहरुख इन दिनों अपने आने वाले प्रॉजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में हैं जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में ऐक्टर की चेन्नई में हुए मैच से कुछ तस्वीरें सामने आईं जिसमें वह साउथ डायरेक्टर ऐटली के साथ दिखे।बता दें, मर्सल एक ऐक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। बात करें शाहरुख की तो वह आखिरी बार डायरेक्टर आनंद एल राय की फिल्म जीरो में अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ के साथ नजर आए थे।

शाहरुख आखिरी बार डायरेक्टर आनंद राय की फिल्म जीरो में अनुष्का और कटरीना के साथ नजर आए थे

चुनाव ड्यूटी पर के सभी स्टाफ को स्वास्थ्य लेकर

स्वास्थ्य बिगड़ने के मौके पर कैशलेस चिकित्सा उपचार

आम चुनाव दौरान चुनाव ड्यूटी पर के सभी स्टाफ को स्वास्थ्य बिगड़ने के मौके पर कैशलेस चिकित्सा उपचार

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, राज्य में आगामी समय में आयोजित लोकसभा आम चुनाव-२०१९ के दौरान चुनाव ड्यूटी पर के सभी स्टाफ को स्वास्थ्य बिगड़ने के मौके पर कैशलेस चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सूची में बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्ताव पारित कराये अनुसार चुनावी कार्य में लगाये गये सभी अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी/अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारी, चुनावी ड्यूटी पर ड्राइवर-क्लीनर (रेक्विजिट किए गए निजी वाहन के ड्राइवर-क्लीनर सहित) चुनावी खर्च नियंत्रण टीमों के विडियोग्राफर सभी स्टाफ को यह कैशलेस उपचार का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की जिला, तहसील स्तर पर आये अस्पतालों तथा मेडिकल संलग्न अस्पतालों, सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चुनावी ड्यूटी पर के स्टाफ को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराई जाएगी। बाहर की दवाईयां, इम्प्लान्ट का खर्च भी अस्पताल द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार की जिला, तहसील स्तर पर आये अस्पतालों तथा मेडिकल संलग्न अस्पतालों, सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चुनावी ड्यूटी पर के स्टाफ को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा यूएन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी सिविल अस्पताल अहमदाबाद, एमपी. शाह कैंसर अस्पताल अहमदाबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में भी नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसका संभावित खर्च री-एम्बर्स करना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्ताव पारित कराये अनुसार चुनावी कार्य में लगाये गये सभी अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारी/अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारी, चुनावी ड्यूटी पर ड्राइवर-क्लीनर (रेक्विजिट किए गए निजी वाहन के ड्राइवर-क्लीनर सहित) चुनावी खर्च नियंत्रण टीमों के विडियोग्राफर सभी स्टाफ को यह कैशलेस उपचार का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की जिला, तहसील स्तर पर आये अस्पतालों तथा मेडिकल संलग्न अस्पतालों, सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चुनावी ड्यूटी पर के स्टाफ को नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराई जाएगी। बाहर की दवाईयां, इम्प्लान्ट का खर्च भी अस्पताल द्वारा दिया जाएगा।बाहर की दवाईयां, इम्प्लान्ट का खर्च भी अस्पताल द्वारा दिया जाएगा।संबंधित जिला चुनावी अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर आपात परिस्थितियों में निकट की निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार मिल सकेगा। यहां उल्लेखनीय है कि, चुनावी ड्यूटी पर के स्टाफ को जब से चुनावी ड्यूटी सौंपी जाए तब से चुनावी ड्यूटी पूरा हो उस दिन तक यह सुविधा मिलेगी यह आगे बताया गया है।

आम चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अहमदाबाद पूर्व के कांग्रेसी उम्मीदवार राजू परमार साइकिल पर प्रचार करने के लिए निकले। (संपूर्ण समाचार सेवा)

नोटिस देने बाद भाजपा के विधायक की बदमाशी

मधु की मीडिया कर्मचारियों को देख लेने की खुली धमकी

विधायक की इतनी ज्यादा बदमाशी होने पर भी पार्टी, पुलिस या शासक क्यों नहीं कार्रवाई करती मुद्दे पर सवाल

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, लोकसभा चुनाव के पहले वाघोडिया के विधायक लगातार विवादों में घिर चुके हैं। चुनाव आयोग ने मधु श्रीवास्तव को नोटिस भेजने के बाद मीडिया कर्मचारियों को इन्टरव्यू लेने के लिए मधु श्रीवास्तव की ऑफिस पर पहुंच गये। जहां मधु श्रीवास्तव ने मीडिया कर्मचारियों को धमकी दी थी कि, मैं मधु श्रीवास्तव हूं, आप जहां नौकरी करते हो वहां से आपको छोड़ना पड़ेगा। भाजपा के विधायक ने बिल्कुल बदमाशी करते मीडियाकर्मचारियों को देख लेने की खुलेआम धमकी देने पर भारी सनसनी मच गई। भाजपा के विधायक की इतनी ज्यादा बदमाशी होने पर भी पार्टी, पुलिस या शासक क्यों नहीं कार्रवाई करती है इस मुद्दे पर सवाल उठाये जा रहे है। लोकसभा सीट के भाजपा के उम्मीदवार चुनाव प्रचार की जनसभा में विधायक मधु श्रीवास्तव ने मतदाताओं को कमल को मत नहीं देंगे तो मार देने की धमकी दी और मीडिया को भी धमकी दी। इसके बाद फिर से मधु श्रीवास्तव ने मीडिया को धमकी दी है। मधु श्रीवास्तव ने नाराज होकर मीडिया कर्मचारियों को बाहर निकालकर उनको देख लेने की धमकी दी। उन्होंने २३ अप्रैल बाद उनके दिन शुरू होंगे और मीडिया को देख लूंगा ऐसी खुली धमकी दी। मधु श्रीवास्तव ने पूरे वडोदरा शहर के वायर काट देने की धमकी दी। उल्लेखनीय है कि, अपने विवादास्पद भाषण मामले में वडोदरा जिला मुख्य चुनाव अधिकारी ने विधायक मधु श्रीवास्तव को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा है, तब ७२ घंटे मे ही मधु श्रीवास्तव मीडिया कर्मचारियों को खुलेआम धमकी देकर नए विवाद में घिर चुके है।

लोकसभा आम चुनाव-२०१९

एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाया गया

(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर, भारत के चुनाव आयोग ने देश में आयोजित होनेवाली लोकसभा के आम चुनाव-२०१९ तथा विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२६-ए की उपधारा (१), (२) के तहत ११.४.२०१९ को सुबह के ७ बजे से १९.५.२०१९ को रविवार के शाम के ६.३० बजे तक के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने या किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रकाशित करना या जारी करना प्रतिबंध लगाया गया है, यह संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयदीप द्विवेदी की सूची में बताया गया है। सूची में आगे बताये अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२६(१) बी के तहत मतदान पूरा होने के घंटे के साथ पूरा होने पर ४८ घंटे के समय दौरान ओपिनियन पोल या मतदान का कोई भी सर्वेक्षण सहित की किसी भी चुनाव संबंधित सामग्री कोई भी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रदर्शित करने प्रतिबंध रहेगा।

वाहनचालकों को आरटीओ प्रशासन द्वारा चेतावनी

ट्राफिक भंग करने पर १५०० नागरिकों के लाइसेंस सस्पेंड

पांच-पांच बार ई मेमो मिलने बाद भी इसे नहीं माननेवाले वाहनचालकों के विरूद्ध आखिर आरटीओ की कार्रवाई

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, सार्वजनिक सड़क पर रोंग साइड वाहन चलाते, चालू वाहन पर मोबाइल फोन पर बात करने वाले या वाट्सएप मैसेज करने वाले या फिर तेजी से वाहन चलानेवाले वाहनचालकों की संख्या बढ़ रही है। पांच-पांच बार ई मेमो मिलने के बावजूद भी इसे नहीं माननेवाले अहमदाबाद आरटीओ ने सख्ती कार्रवाई की थी। वर्ष २०१८-१९ में आरटीओ ने करीब १५०० से ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। आरटीओ प्रशासन ने यह कार्रवाई द्वारा शहर में ट्राफिक नियमों का भंग करने वाले वाहनचालकों के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। आरटीओ के सख्त रवैये को लेकर अब शहरीजनों को ट्राफिक नियमों के पालन और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता होनी चाहिए। आरटीओ ने दोषी वाहनचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करके इसमें वाहन दुर्घटना करने वाले भी शामिल है। वाहनचालक मोबाइल पर बात करते, गाडी चला रहे हो, पीये हो या फिर तेजी से वाहन चला रहे हो उन पर सख्त रवैया अपनाकर आरटीओ और ट्राफिक पुलिस कार्रवाई करती है। ट्राफिक पुलिस अधिकतर आरटीओ को ऐसे वाहनचालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए सिफारिश करती है। सामान्य रूप से आरटीओ वाहनचालक का सीधा लाइसेंस सस्पेंड नहीं करती है। दुर्घटना के अलावा केस में आरटीओ पहले वाहनचालक को सुनती है। जिसके खिलाफ सरकार ने भी अब नाराजगी व्यक्त की है अब वाहनचालक नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क किया होगा या रोंग साइड वाहन चला रहे होंगे या सीट बेल्ट बिना वाहन चला रहे होंगे तो भी आरटीओ उनका लाइसेंस सस्पेंड कर सकती है यह आरटीओ विभाग के सूत्रों ने बताया है।

गर्मी का प्रमाण बढ़ रहा है तब जमालपुर एपीएमसी मार्केट के बाहर व्यापारी बड़े छाते के नीचे कारोबार कर रहे है। (संपूर्ण समाचार सेवा)

वसुंधरा राजे बैंसला के पार्टी में शामिल होने से नाराज

गुर्जर नेता बैंसला और उनके बेटे विजय बीजेपी में शामिल

बैंसला ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की

(संपूर्ण समाचार सेवा) जयपुर,

२०१४ लोकसभा चुनाव की तर्ज पर राजस्थान में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी जोर-शोर से सूबे में प्रचार अभियान में जुटी है। दरअसल, विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी का फोकस अब राजस्थान पर है। पार्टी २०१४ के लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन यहां दोहराना चाहती है। इसके लिए पार्टी यहां हर वर्ग को साधने में जुटी है। इसी क्रम में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला के साथ बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की वरिष्ठ नेता और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैंसला के पार्टी में शामिल होने को लेकर नाराज हैं। उधर बीजेपी में शामिल होने से पहले बैंसला ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। दरअसल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों में हुई हार के बाद पार्टी ने तीनों राज्यों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तीनों ही राज्यों में पार्टी अब हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों राजस्थान के मारवाड़ इलाके में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल एनडीए (नैशनल डेमोक्रैटिक अलायंस)में शामिल होने का ऐलान किया था। इसके बाद से ही यह अटकलें भी तेज हो गई थी कि बैंसला भी जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी मारवाड़ इलाके के नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली और सीकर जिलों में आरएलपी का जनाधार माना जाता है। इस बेल्ट की कई सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। सके लिए पार्टी यहां हर वर्ग को साधने में जुटी है। इसी क्रम में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अपने बेटे विजय बैंसला के साथ बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी की वरिष्ठ नेता और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैंसला के पार्टी में शामिल होने को लेकर नाराज हैं। उधर बीजेपी में शामिल होने से पहले बैंसला ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात की। दरअसल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों में हुई हार के बाद पार्टी ने तीनों राज्यों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तीनों ही राज्यों में पार्टी अब हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों राजस्थान के मारवाड़ इलाके में असर रखने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। यही वजह है कि बेनीवाल के आने से बीजेपी को इस क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर लाभ मिल सकता है। गुर्जर नेता बैंसला सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ५ प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं। फरवरी में अपनी मांग को लेकर समर्थकों के साथ सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में रेल पटरी पर बैठ गए थे। बाद में करौली जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनके घर के बाहर एक नोटिस चस्पा करना पड़ा। करौली के जिला कलेक्टर ननूमल पहाड़िया ने तब कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सड़क और रेल मार्ग को अवरूद्ध करना न्यायालय की अवमानना है।

सरकार को मिले २७६८ जवान और ३८९ वाहन

२२ अलगाववादियों समेत ९१९ लोगों की सुरक्षा वापस

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

जम्मू-कश्मीर में बीते दिनों अलगाववादी नेताओं समेत तमाम लोगों से सुरक्षा वापस लेने के बाद अब राज्य पुलिस को २७०० से अधिक पुलिसकर्मी वापस मिल गए हैं। अब तक यह पुलिसकर्मी अलग-अलग लोगों की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे, जो कि अब आम लोगों की सुरक्षा के लिए विभिन्न इलाकों में भेजे जाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा वापसी के कारण पुलिस विभाग को ३८९ ऐसे वाहन भी वापस मिले हैं, जो कि अब तक अलग-अलग लोगों के काफिले में सुरक्षा के लिहाज से शामिल रहते थे। बुधवार को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए यह आंकड़े जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है,जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद कुल ९१९ अपात्र लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है। इन लोगों में २२ प्रमुख अलगाववादी भी शामिल हैं, जिनसे बीते दिनों सुरक्षा वापस मांग ली गई थी। सुरक्षा वापसी के निर्णय के बाद केंद्र सरकार को २७६८ पुलिसकर्मी और ३८९ वाहन वापस मिले हैं। अब इन सभी का इस्तेमाल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में किया जाएगा। बता दें कि पूर्व में सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों और अलगाववाद में शामिल रहने के आरोपी कश्मीर के तमाम नेताओं और अन्य लोगों की सुरक्षा की समीक्षा करने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, अगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, यासीन मलिक, सलीम गिलानी, शाहिद उल इस्लाम, जफर अकबर भट, नईम अहमद खान, फारुख अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, अगा सैयद अब्दुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह, मोहम्मद मुसादिक भट और मुख्तार अहमद वजा समेत कई अन्य की सुरक्षा वापस ली थी। इन लोगों में २२ प्रमुख अलगाववादी भी शामिल हैं, जिनसे बीते दिनों सुरक्षा वापस मांग ली गई थी। सुरक्षा वापसी के निर्णय के बाद केंद्र सरकार को २७६८ पुलिसकर्मी और ३८९ वाहन वापस मिले हैं। अब इन सभी का इस्तेमाल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में किया जाएगा। इन सभी लोगों को सुरक्षा ड्यूटी में तैनात जवानों और वाहनों को सरकार को वापस करने के निर्देश दिए गए थे।

राफेल मामले पर बोले राहुल गांधी

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार ने कराई चोरी

राहुल ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे १५ मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे

(संपूर्ण समाचार सेवा) अमेठी,

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी संसदीय सीट अमेठी से नामांकन भरने के बाद राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि डील में करप्शन हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। राहुल ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे १५ मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। बता दें कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। राहुल ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, पीएम नरेन्द्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा कि राफेल मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। राहुल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। राफेल में दो लोगों ने ही भ्रष्टाचार किया है, एक नरेन्द्र मोदी और दूसरा अनिल अंबानी। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पीएम नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, चौकीदार जी ने देश का पैसा अनिल अंबानी को दे दिया। वह मुझसे १५ मिनट के लिए भ्रष्टाचार पर बहस कर लें, मैं तैयार हूं। वह जहां चाहे वहां बहस के लिए बुलाएं। ाफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। वह एक बार मुझसे बहस कर लेंगे तो देश से आंख नहीं मिला पाएंगे। बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली ३ सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि राफेल मामले में जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। राहुल ने कहा कि एक बार पीएम मोदी उनसे १५ मिनट बहस कर लेंगे तो देश से भी आंख नहीं मिला पाएंगे। बता दें कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का आदेश दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। राहुल ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, पीएम नरेन्द्र मोदी ने अभी टीवी इंटरव्यू में कहा कि राफेल मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया।बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं।

मतदान सात बजे शुरू होकर शाम छह बजे तक

पहले चरण का मतदान आज : तय होगा कई दिग्गजों का सियासी भाग्य

सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीटों के लिए मतदान

(संपूर्ण समाचार सेवा) लखनऊ,

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के पश्चिमाञ्चल स्थित आठ सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा। मतदाता सुबह ७:०० बजे से शाम ६:०० बजे तक वोट डाल सकेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. वेंकटेश्वर लू ने बताया कि पहले चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर शाम छह बजे तक चलेगा। इस चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में डेढ़ करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें ८२,२४,००० पुरुष तथा ६८,३९,००० महिलाएं शामिल हैं। इस चरण के लिए कुल ६,७१६ मतदान केंद्र और १६,५८१ मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों जनरल वीके सिंह (गाजियाबाद) तथा महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर) के साथ साथ रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह (मुजफ्फरनगर) और उनके बेटे जयंत चौधरी (बागपत) समेत कई दिग्गजों का सियासी भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगा। पहले चरण में मुजफ्फरनगर सीट पर सपा-बसपा-रालोद महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर रालोद प्रमुख अजित सिंह का मुकाबला भाजपा के मौजूदा सांसद संजीव बालियान से होगा। बागपत सीट पर अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। वहां उनका मुकाबला मौजूदा सांसद भाजपा के सत्यपाल सिंह और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी मोहकम से है। गाजियाबाद सीट पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश बंसल और कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा से है। नोएडा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के सामने लगातार दूसरी बार इस सीट से संसद पहुंचने की चुनौती है। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने डॉ अरविंद सिंह को उतारा है जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सत्यवीर नागर मैदान में हैं। सहारनपुर में मौजूदा भाजपा सांसद और प्रत्याशी राघव लखन पाल का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के इमरान मसूद से है। पिछले साल हुए उपचुनाव में भाजपा से कैराना की सीट छीनने वाली मौजूदा सांसद और महा गठबंधन की प्रत्याशी तबस्सुम हसन के सामने एक साल के अंदर इस सीट को दूसरी बार जीतने की कड़ी चुनौती है। उनका मुख्य मुकाबला गंगोह सीट से मौजूदा विधायक भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी तथा कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक से है। मेरठ सीट पर मौजूदा भाजपा सांसद और प्रत्याशी लगातार तीसरी बार जीतने की आस लगाए हुए हैं। बसपा ने यहां से महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के बेटे हरेंद्र अग्रवाल को टिकट दिया है। बिजनौर सीट पर मौजूदा भाजपा सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। उनका मुकाबला कभी बसपा प्रमुख मायावती के विश्वसनीय रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी से है। वहीं, महागठबंधन ने मलूक नागर को यहां से मैदान में उतारा है। मतों की गिनती २३ मई को की जाएगी।

जूनागढ़ में बोले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

कांग्रेस के घोटालों में जुड़ा तुगलक रोड चुनावी घोटाला

कांग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन भर एक ही गाना बजता है

मोदी हटाओ, मोदी हटाओ : मोदी का कांग्रेस पर निशाना

(संपूर्ण समाचार सेवा) जूनागढ़,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के घर से आयकर के छापे में करोड़ों रुपये बरामद होने के बहाने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेसियों के पास से बोरा भर-भर के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। कांग्रेस ने पहले कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया, अब मध्य प्रदेश भी कांग्रेस का एटीएम बन गया है। कांग्रेस के घोटालों में एक नया घोटाला सबूतों के साथ और जुड़ गया है। वह है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। गुजरात के जूनागढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सरदार पटेल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मोदी जब आतंकवाद हटाने की बात करता है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को हटाने की बात करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो इन्होंने आपके इस बेटे को न दी है। क्या जूनागढ़ और सोमनाथ का व्यक्तिसरदार साहब को भूल सकता है ? सोचिये अगर सरदार साहब न होते तो जूनागढ़ कहां होता ? उन्होंने कहा, जब मोराजी देसाई उभर कर आए तो इन्हें उनके लिए भी नफरत हो गई। सिद्धांतों के लिए जीने वाले मोराजी की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। अब इन्हें मुझसे मुसीबत है कि एक चायवाले ने पूरे दमखम से पांच साल कैसे निकाल दिए। कांग्रेस के टेप रिकॉर्डर पर दिन भर एक ही गाना बजता है- मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी हटाने के सिवाय इनके पास कोई अजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज सरदार पटेल के सपनों के साथ-साथ हर हिन्दुस्तानी की भावना को चोट पहुंचा रही है। यह वही कांग्रेस है जिसे सरदार पटेल ने अपने पुरुषार्थ से सींचा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लूटने के लिए सत?ता में आती है लेकिन आपका चौकीदार चौकन्ना है। उन्होंने कहा, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। मीडिया में दिख रहा है कि कांग्रेसियों के पास से बोरा भर-भर के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। कांग्रेस ने पहले कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया, अब मध्य प्रदेश भी कांग्रेस का एटीएम बन गया है। बता दें कि आयकर विभाग ने सोमवार को कहा था कि उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगियों और अन्य के खिलाफ की गई छापेमारी के दौरान करीब २८१ करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी के विस्तृत एवं सुसंगठित रैकेट का पता लगाया है। विभाग ने बताया कि अधिकारियों ने १४.६ करोड़ रुपये की 'बेहिसाबी' नकदी बरामद की है और मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के बीच हुए संदिग्ध भुगतान से जुड़ी डायरी तथा कंप्यूटर फाइलें अपने कब्जे में ली हैं। उधर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा था कि विभाग को २० करोड़ रुपये की संदिग्ध नकदी के तुगलक रोड पर रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर से दिल्ली की बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय तक कथित तौर पर जाने के सुराग भी मिले हैं। हालांकि उसने न तो राजनीतिक पार्टी की और न ही वरिष्ठ पदाधिकारी की पहचान उजागर की। सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा था, अब तक शराब की २५२ बोतलों, कुछ हथियारों और बाघ की खाल के अलावा १४.६ करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी मिली है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करती है।

चुनाव आयोग ने रिलीज पर लगाई रोक

मोदी की बायॉपिक 'पीएम नरेन्द्र मोदी' की रिलीज पर लगी रोक

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा था

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

आनेवाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायॉपिक वाली फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' की रिलीज पर चुनाव आयोग की तरफ से रोक लगा दी गई है। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से 'यू' सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोके जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा था। दरअसल फिल्म पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक की रिलीज पर लोकसभा चुनाव के अंत तक रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता जो चुनाव में सभी दावेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो। इससे पहले ९ अप्रैल की सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विशेष याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान फिल्म की रिलीज पर अस्थायी तौर पर बैन लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अभी तक सेंसर बोर्ड (CBFC) ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है और फिल्म देखना उन्हीं का काम है। साथ ही, अगर इस फिल्म के कारण चुनाव कराने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर भी केवल चुनाव आयोग ही यह फैसला ले सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर यह फिल्म आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोके जाने के लिए दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया था और फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा था। दरअसल फिल्म पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायॉपिक की रिलीज पर लोकसभा चुनाव के अंत तक रोक लगा दी। आयोग ने कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाया जा सकता जो चुनाव में सभी दावेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो। इससे पहले ९ अप्रैल की सुबह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विशेष याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान फिल्म की रिलीज पर अस्थायी तौर पर बैन लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, इसी बीच फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से 'यू' सर्टिफिकेट दिया गया था और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता का आरोप था कि फिल्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH